बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 264

एनआरसी पर स्पष्टीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्ताहांत पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर जो बातें कहीं उनसे देश की जनता में भ्रामक संदेश गया है।

इस विषय पर तत्काल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एनआरसी और हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन से परेशान मोदी ने दिल्ली में एक चुनावी सभा में तीन बातें कहीं।

पहला, उन्होंने दावा किया कि असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में यानी देशव्यापी स्तर पर एनआरसी लागू करने को लेकर कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं हुई। बीते पांच वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ।

दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एनआरसी के लिए न तो कोई नियम जारी किए गए हैं और न उन पर संसद में चर्चा हुई है।

तीसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे अमल में लाने के लिए कोई डिटेंशन कैंप (नजरबंदी शिविर) नहीं बनाए गए हैं। परंतु इन तीनों मोर्चों पर मोदी की बात सच नहीं है।

संसद का 20 नवंबर का रिकॉर्ड बताता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में असम में समाप्त विवादास्पद एनआरसी प्रक्रिया के तर्ज पर देश भर में एनआरसी लागू करने का सरकार का इरादा जाहिर किया था।

शाह दरअसल 1 मई के अपने ट्वीट को ही दोहरा रहे थे कि पहले सीएए और उसके बाद एनआरसी आएगा। उन्होंने कहा था कि देश से हर घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा। मई में हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी पार्टी के घोषणापत्र में एनआरसी का प्रमुखता से उल्लेख किया गया था।

इसके अलावा यदि ऐसी कोई पहल नहीं की गई होती तो क्या भाजपा के अन्य बड़े नेताओं से जवाब तलब नहीं किया गया होता? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 दिसंबर को इस संबंध में वक्तव्य दिया था। कर्नाटक जिसने अक्टूबर में कहा था कि वह एनआरसी लागू नहीं करेगा, उसके बारे में जानकारी है कि वहां मार्च 2020 से यह कवायद शुरू करने की चर्चा हुई है। मोदी का यह कहना भी भ्रामक है कि मामला न तो संसद में आया है और न ही नियम बने हैं।

एनआरसी को संसद में लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संबंधित कानून 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पारित हो गया था और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नामांकन के रूप में प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। जहां तक डिटेंशन सेंटर की बात है तो गुवाहाटी, नवी मुंबई, बेंगलूरु और पश्चिम बंगाल में दो स्थानों पर इसके निर्माण के लिए जगह चिह्नित कर ली गई है।

सच्चाई और वक्तव्य में इतनी विसंगति से आम जनता की चिंता दूर होने वाली नहीं है। यह संभव है कि मोदी ने भाजपा के सहयोगियों समेत व्यापक विरोध से निकले संदेश को समझ लिया हो और उन्हें लगा हो कि जनता का मिजाज ठीक से समझ नहीं पाए।

भारी बहुमत पाने के बाद अक्सर नेताओं से ऐसी चूक हो जाती है। चूंकि वह सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए संभव है रैली में उनका वक्तव्य इस बात का संकेत हो कि फिलहाल के लिए एनआरसी को टाल दिया गया हो। यदि ऐसा है तो लाखों नागरिकों को अनिश्चितता में धकेलने के बजाय इस विषय में स्पष्ट वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए।

यकीनन पांच वर्ष तक बहुसंख्यकवादी बातों को दोहराने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से यह सुनना वाकई अच्छा लगा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यदि वह देश के इस बुनियादी मूल्य पर अमल करने का निर्णय करें तो और भी बेहतर होगा।

अजय मोहंती

वित्तीय क्षेत्र में रेटिंग सुधारने का तिलिस्म

किसी देश की रेटिंग का ताल्लुक सेवा क्षेत्र को ऋण देने की उसकी क्षमता एवं उत्सुकता से बुनियादी तौर पर होना चाहिए। इसकी अहमियत बता रहे हैं **टी टी राम मोहन**

रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स (एसऐंडपी) ने भारत के लिए चेतावनी जारी कर दी है: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की हालत सुधारें या रेटिंग में कटौती के लिए तैयार रहें। मूडीज ने पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को 'स्थिर' से बदलकर 'नकारात्मक' कर दिया है। एसऐंडपी ने वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि के 5.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने आर्थिक वृद्धि दर के इस साल 4.9 फीसदी रहने की बात कही है। महज दो साल पहले किसने सोचा होगा कि भारत की जीडीपी वृद्धि छह फीसदी से भी नीचे आ जाएगी?

संभावित डाउनग्रेड की चेतावनी देने के लिए रेटिंग एजेंसियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। खबरों का प्रवाह काफी डरावना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अक्टूबर में 3.8 फीसदी ऋणात्मक रहा था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई नवंबर में एक साल पहले की तुलना में 5.5 फीसदी बढ़ गई। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 3.3 फीसदी रहने के बजट लक्ष्य से पार जाना तय ही है। वित्तीय क्षेत्र में तनाव बरकरार है। कर्ज लेने की दर काफी गिर चुकी है।

एजेंसियों ने अच्छे वक्त में भी भारत को रेटिंग देने के मामले में गलती की है। आर्थिक समीक्षा 2016-17 में कहा गया था कि भारत एसऐंडपी से मिली बीबीबी रेटिंग से बेहतर का हकदार है क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन काफी अच्छा था। एक देश की रेटिंग सेवा ऋण के मामले में उसकी क्षमता एवं उत्सुकता से संबंधित होनी चाहिए। भारत ने बीते वर्षों में अपनी कर्ज देनदारियों में चूक नहीं की है। इसका कर्ज एवं जीडीपी के बीच करीब 65 फीसदी का अनुपात ऊंचा लग सकता है। लेकिन इसे जीडीपी में बाह्य ऋण के अनुपात और इसकी वृद्धि दर के तारतम्य में ही देखा जाना चाहिए। क्या विदेशी लेनदारों को यह लगता है कि आज भारत पर अपनी कर्ज देनदारी पूरा नहीं कर पाने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हमारी वृद्धि दर फिसल चुकी है? यह सुझाव हंसी के लायक ही लगता है।

यह ठीक है कि रेटिंग एजेंसियां कहीं नहीं जाने वाली हैं और रेटिंग में गिरावट हमेशा ही एक सिरदर्द होता है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती यह है कि बढ़ी हुई वृद्धि दर दोबारा हासिल की जाए। घाटे के मौजूदा स्तर के हिसाब से देखें तो राजकोषीय राहत देना असंभव नजर आता है। सार्वजनिक इकाइयों (पीएसयू) की परिसंपत्तियों की त्वरित बिक्री कर राजस्व जुटाने की चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं है। रणनीतिक बिक्री में मूल्य-निर्धारण एवं बोली लगाने की कठिन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। और वे विवाद से उस समय भी परे नहीं हैं। एयर इंडिया की बिक्री की एक कोशिश 2018 में नाकाम हो गई थी लेकिन अब भी इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर की समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती रोक दी है जिससे मौद्रिक सुगमता भी नहीं रह गई है। फिलहाल यह कोई बड़ा मसला नहीं है। यह अधिक अहम है कि अब तक नीतिगत दरों में हुई 135 आधार अंकों की कटौती का कितना हिस्सा नीचे तक पहुंचा है? जमाओं में अचलता असल में पारेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरे कारक भी हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उधारी देने में हिचक सकते हैं क्योंकि कई बैंक न्यूनतम पूंजी जरूरत के करीब काम कर सकते हैं। तेरह सार्वजनिक बैंक विलय के व्यापक दौर से गुजर रहे हैं। इससे भी कर्ज आवंटन में कुछ सुस्ती आई है।

इस तरह अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए दो बड़े वृहद-आर्थिक उपकरण-राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन कुंद हो चुके हैं। लिहाजा सरकार क्षेत्रवार स्तर पर मुद्दों का समाधान करने पर ध्यान देने के मामले में सही है। वित्तीय क्षेत्र में तनाव को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में दो तरह की अच्छी खबरें हैं। पहली, एस्सार मित्तल का आर्सेलरमित्तल द्वारा अधिग्रहण हो रहा है और इससे बैंकों को 42,000 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। एस्सार स्टील को कर्ज देने वाले बैंक अपना बकाया मिलने पर किए गए ऋण प्रावधान को हटा सकते हैं। दूसरी, बैंकों को टाटा समूह, आईसीआईसीआई बैंक और वैश्विक निवेशकों के स्वामित्व वाली इकाई के हाथों प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी की बिक्री से 6,000 करोड़ रुपये मिले हैं। एकमुश्त समाधान में ऋणदाताओं को इस सौदे में 52 फीसदी नुकसान झेलना था। यह विचित्र है कि इस सौदे का वित्तपोषण भारतीय स्टेट बैंक ने किया है जो खुद नुकसान उठाने वाले बैंकों में शामिल है। अगर बैंकर दिवालिया प्रक्रिया के बाहर बड़ी कर्जदार संपत्तियों के समाधान की कोशिश के लिए आखिर साहस जुटा रहे हैं तो यह एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने सही संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंकरों के वैध कारोबारी निर्णयों पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे।

किफायती एवं मध्यम आय वाली आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) सक्रिय हो चुका है। इस कोष के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। एनबीएफसी की परिसंपत्तियां खरीदने के लिए बैंकों को आंशिक ऋण गारंटी देने की योजना भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने करीब एक लाख करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना के मद में सरकार ने 7,657 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत उपलब्ध आंशिक ऋण गारंटी का दायरा बीबीबी रेटिंग वाले एनबीएफसी तक बढ़ा दिया है। पहले यह सुविधा केवल एए या उससे अधिक रेटिंग वाले एनबीएफसी के लिए ही उपलब्ध थी।

दोनों योजनाओं से राहत मिलनी चाहिए लेकिन एक स्तर तक ही ऐसा होगा। एआईएफ के लिए आवंटित राशि काफी कम है और इस योजना को लागू कर पाना भी आसान नहीं है। आंशिक ऋण गारंटी भी बैंकों को बाहर निकलकर एनबीएफसी की परिसंपत्तियां लेने के लिए नहीं उत्साहित करेगी। बैंक इस कर्ज के बड़े हिस्से को लेकर आशंकित होंगे क्योंकि वह असुरक्षित उपभोक्ता कर्ज हैं। रियल एस्टेट कर्जों में आवासीय परियोजनाओं के कर्ज, पट्टा किराया छूट, वाणिज्यिक परिसर और डेवलपर वित्त का जोड़ है। बैंक पहले दो समूहों के प्रति रुचि दिखाएंगे लेकिन इन दोनों उत्पादों के लिए खासी मांग पहले से ही है। ऐसे में बैंकों को एनबीएफसी से ऋणग्रस्त परिसंपत्तियां खरीदने की जरूरत नहीं महसूस हो सकती है। आर्थिक वृद्धि की फिसलन मूलत: इस वजह से आई है कि एक बैंकिंग संकट के बाद एनबीएफसी संकट भी आ गया है। एनबीएफसी क्षेत्र को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना एक लंबी कवायद होने जा रही है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए ध्यान बैंकों पर होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समुचित पूंजी डालना, शीर्ष स्थानों पर त्वरित नियुक्तियां सुनिश्चित करना और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रबंधन को सशक्त करना स्थिति को तेजी से ठीक करने के लिए बेहद जरूरी हैं।

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं)

अस्वाभाविक समय में भी नैसर्गिक साझेदार हैं अमेरिका और भारत

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पांपेओ और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर तथा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात के बाद अमेरिकी मीडिया ने जम्मू कश्मीर संकट और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर लगातार सवाल किए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत को लेकर अमेरिकी अवधारणा बनाने में ये मुद्दे अहम हैं।

दो दशक पहले दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आने के बाद बार-बार इनके 'नैसर्गिक साझेदार' होने की बात कही जाती है। लगभग हर साझे वक्तव्य में 'साझा मूल्यों' और 'जीवंत लोकतंत्र' होने की बात कही गई है। व्यावहारिक राजनीति करने वाले कहते हैं कि यह बस जुमलेबाजी है क्योंकि अमेरिका का तानाशाहों और अलोकतांत्रिक नेताओं के समर्थन का इतिहास रहा है। अमेरिका जहां दबंग नेताओं और उनके अधिनायकवादी शासन के साथ नीतिगत समझौते करता रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ उसके समझौते साझा मूल्यों और वैश्विक दृष्टि पर आधारित हैं।

कुछ का कहना है कि ट्रंप भारत पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि वह खुद 2017 में चुनिंदा मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर रोक लगा चुके हैं। उनके इस प्रतिबंध को अमेरिकी अदालतों ने तो उलटा ही, अमेरिकी मीडिया, समाज और वहां के सदन के सदस्यों ने भी खारिज किया। ट्रंप अमेरिकी नीति में एक असामान्य घटना हैं। यदि वह 2021 में जीतते हैं तो जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति रहेंगे। यह बात सीनेट में भी प्रतिध्वनित हुई जब प्रतिनिधि सभा में उन पर महाभियोग चलाने की बात उठी।

अमेरिका ने अब तक भारत में मुस्लिमों के विरुद्ध भेदभाव करने या कश्मीरी नेताओं को बंदी बनाए रखने को लेकर कुछ नहीं कहा था। हालिया संवाद में अवश्य पांपेओ ने कहा कि अमेरिका हर जगह अल्पसंख्यकों के संरक्षण और धार्मिक अधिकारों के बचाव को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में इन मसलों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया में निरंतरता रहेगी। भारत की लाज बचाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करता है क्योंकि भारत में खुद इन विषयों पर बड़ी बहस चल रही है।

बहरहाल, भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर अमेरिकी प्रशासन को एक नई तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर अमेरिकी कांग्रेस में भारत के साथ रिश्ते को लेकर द्विपक्षीय सहमति पर भी पड़ेगा। माना जा सकता है कि भारत होने के नाते हमें अमेरिका से जो सहूलियतें मिलती थीं वे बंद हो सकती हैं। भारत के लिए रूस एस-400 हवाई रक्षा मिसाइल खरीदने को अमेरिकी इजाजत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। वहीं कई मुद्दों पर अब भारत को खुलकर अमेरिका के साथ आना होगा, भले ही भारत के हित उस कदर जुड़े हों या नहीं।

विदेश और रक्षा मंत्रियों के उपरोक्त संवाद के नतीजे आशा के अनुरूप ही थे। अमेरिका ने हिंद-प्रशांत में भारत की सुरक्षा स्थिति का समर्थन किया। भारत ने भी उस सुरक्षा ढांचे का समर्थन करते वक्त चीन की आवश्यकताओं का ध्यान रखा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत के योगदान की सराहना की लेकिन तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता इस बात से विरोधाभासी है। अमेरिका ने ईरान के मसले पर भारत से कहा कि वह अधिकतम दबाव में सहयोग करे। हालांकि उसने भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर सहयोग को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने चीन के 5जी संचार नेटवर्क पर चिंता जताई जबकि भारत के मंत्री खामोश रहे। रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में और प्रगति देखने को मिली। औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर अहम हैं। इसके तहत भारत को अहम अमेरिकी रक्षा तकनीक हासिल होगी। दोनों देशों के रक्षा उद्योग में करीबी संबंध कायम होंगे। इस संबंध में वार्ता सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। इससे पहले के दो समझौतों को पूरा होने में एक दशक लगा था।

ऐसे में बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौते (बीईसीए) के रूप में एक ही ऐसा समझौता शेष है जो भारत और अमेरिकी सेना के बीच जानकारियां साझा करने की व्यवस्था को सुसंगत बनाएगा। इससे नेविगेशन और निशाना तय करने की व्यवस्था बेहतर होगी। भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी मंच के सलाहकार विक्रम सिंह कहते हैं कि उम्मीद थी कि बीईसीए को जल्दी मूर्त रूप दिया जा सकगा लेकिन अभी भी चिंता के तमाम विषय बरकरार हैं।

रक्षा रिश्तों में दोनों पक्षों ने रक्षा तकनीक और व्यापार पहल (डीटीटीआई) के तहत तीन समझौतों को अंतिम रूप देने की घोषणा की। इसके तहत अहम तकनीक विकसित की जाएंगी। दोनों देशों के रक्षामंत्रियों और नई दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना मुख्यालय तथा हवाई स्थित इंडो-यूएस पैसिफिक कमांड के बीच हॉटलाइन का काम पूरा होने की घोषणा भी की गई। बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक बल की केंद्रीय कमान में एक भारतीय नौसेना अधिकारी की तैनाती की घोषणा भी की गई।

दोनों देश हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों पर करीबी नजर रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे के यहां अधिकारियों की तैनाती कारगर होगी। इस पर भी सहमति बनी कि अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमांड और अफ्रीकी कमांड के अधिकारियों को साझा प्रशिक्षण दिया जाए।

दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्यिक मसलों पर असहमति के बावजूद रक्षा रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। पारंपरिक तौर पर देखें और पाकिस्तान का उदाहरण लें तो अमेरिका मानवाधिकार और राजनीतिक तथा धार्मिक आजादी पर सुरक्षा साझेदारी चिंताओं को तरजीह देता है। परंतु भारत के लिए यह बेहतर होगा कि वह सहिष्णुता की परीक्षा न ले और उन मूल्यों की ओर लौटे जो अंतरराष्ट्रीय जगत में उसे प्रभावी और स्वीकार्य बनाए रखते थे।

कानाफूसी

मध्य प्रदेश के नाखुश विधायक

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पहली बार विधायक बने 15 नेताओं ने मंत्रियों और अफसरशाहों की बेरुखी से नाखुश होकर एक दबाव समूह बनाया है। उनका इरादा आगे नियमित बैठकें करने और अपनी मांगों, अनुशंसाओं पर उठाए गए कदमों की समीक्षा करने का है। इन नेताओं का यहां तक कहना है कि अगर भविष्य में हालात नहीं सुधरे तो वे अपनी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ तक पहुंचाएंगे। नाराज विधायकों में संजय शुक्ला, सुरेंद्र सिंह शेरा, अशोक मर्शकोले और भूपेंद्र मरावी समेत कई नाम शामिल हैं। वहीं ये विधायक जिन मंत्रियों से प्रसन्न हैं और जिनके यहां इन्हें अधिक तवज्जो मिलती है उनकी भी सूची बनाई गई है। ऐसे मंत्रियों में शहरी विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और वन मंत्री उमंग सिंघार शामिल हैं।

स्टालिन या रजनीकांत?

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन के बेटे और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष उदयनिधि स्टालिन को सोशल मीडिया पर रजनीकांत का विरोध करने के कारण राजनीतिक विरोधियों और रजनीकांत के प्रशंसकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। रजनीकांत ने ट्विटर पर लोगों को सलाह दी कि वे हिंसा न करें और एकजुट रहें। हालांकि उन्होंने ट्वीट में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन का उल्लेख नहीं किया। उधर लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ द्रमुक के आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करते हुए जूनियर स्टालिन ने 69 वर्षीय अभिनेता रजनीकांत पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि जो बूढ़े लोग अधिकारों के लिए हो रहे प्रदर्शन को हिंसा का नाम दे रहे हैं, वे सुरक्षा के साथ अपने घर पर बैठे रहें। इस पर लोगों ने उदयनिधि से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह अपने पिता की बात कर रहे हैं क्योंकि वह भी 66 वर्ष के हैं।

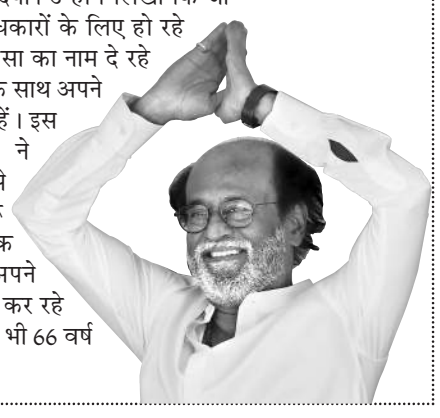

आपका पक्ष

सड़क हादसे रोकने के लिए हों उपाय

देश में सड़क हादसों में एक दिन में जितने लोग जान गंवाते हैं उतने तो आतंकवाद के शिकार नहीं होते हैं। सरकार को सड़क हादसे रोकने के लिए भी उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना कि देश की सुरक्षा के लिए आतंकवाद को लेकर है। सड़क हादसा कभी किसी की लापरवाही से हो जाता है तो कभी दूसरों की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ जाती है। दोपहिया वाहनों की दुर्घटना के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने वालों को हमेशा हेलमेट पहन कर वाहन चलाना चाहिए। केवल चालान भरने के डर से हेलमेट पहनने की आदत बदलनी चाहिए। सरकार सड़क हादसे रोकने के लिए कानून बनाती है लेकिन इस कानून का पालन वाहन चालकों को करना पड़ेगा। यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान काटने का मकसद किसी चालक को परेशान करना नहीं होता है, बल्कि सरकार का मकसद उन लोगों को सबक सिखाना होता है जो यातायात नियम तोड़ कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। सड़क पर सावधानी, सतर्कता और यातायात नियमों के पालन से स्वयं तथा दूसरों की कीमती जान को बचाया जा सकता है। अपनी लापरवाही से जब कोई दुर्घटना होती है तो लोग सरकार को दोष देने लगते हैं। अगर हम खुद ही लापरवाही बरतेंगे और हादसों का कारण बनेंगे तो सरकार इस मामले में क्या कर सकती है। सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई कानून नहीं होता है कि एक छोटे से वाहन में संख्या से अधिक यात्रियों को बिठा दिया जाए। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए आम लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। जिन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने का तजुर्बा न हो वे वाहन न चलाएं और जिस वाहन में सीटों की संख्या जितनी हो उसमें उतनी सवारी बिठाई जानी चाहिए। अगर कोई निजी वाहन चालक सीटों की संख्या से अधिक यात्रियों को वाहन में चढ़ाता है तो यात्रियों को ऐसे वाहन में बैठने से मना कर देना चाहिए। अगर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार को विशेष उपाय करने चाहिए

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

ट्रंप के गले का फांस बना महाभियोग

वर्ष 2020 का अमेरिकी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के चलते अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का भी पूरा जोर ट्रंप को हराने पर है। ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपतियों एंड्रू जॉनसन व बिल क्लिंटन को महाभियोग से क्लीन चिट मिल गई थी वैसे ही ट्रंप को भी इस महाभियोग से क्लीन चिट मिल जाएगी। मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग सफल होते देखकर त्यागपत्र दे दिया था। विपक्षी प्रत्याशी जो बाइडन पर यूक्रेन के जरिये चरित्र हनन कराने का आरोप लग रहा है इसी तरह वर्ष 2016 के चुनाव को रूस के जरिये प्रभावित कराने का आरोप लग चुका है। प्रतिनिधि सभा में विपक्षियों को बहुमत हासिल है लेकिन सीनेट में नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद ट्रंप के क्रियाकलापों से खासे नाराज हैं और इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।